GOVERNMENT BILLS — *Contd*.

The Delhi High Court (Amendment) Bill, 2014

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, at 2.00 p.m. Now, the Delhi High court (Amendment) Bill, 2014. Shri Sadananda Gowda. There is only half-an-hour for this Bill. The Minister will also take five minutes. We have to pass it in half-an-hour.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Mr. Deputy Chairman, Sir, I move:

> That the Bill further to amend the Delhi High Court Act, 1966 be taken into consideration.

The Delhi High Court Act of 1966 was enacted by Parliament determining the constitutional jurisdiction of the Delhi High Court. The pecuniary jurisdiction of the District Courts of Delhi is provided in Punjab High Court Act, 1918. Sub-section (2)(a) of Section 1 of the said Act extends the said Act to the Union Territory of Delhi. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please continue. ...(*Interruptions*)... Please order. Those who are talking, please take your seat. You cannot talk at the passage, please. All of you take your seat. Please, please.

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: The pecuniary jurisdiction of Delhi High Court and Delhi District Court was last revised from rupees five lakh to rupees twenty lakh by Delhi High Court (Amendment) Act, 2003 by amending Section (2) of Section 5 of the Delhi High Court Act and Section 25 of the Punjab High Court Act, 1918. The Coordination Committee of the Delhi Bar Association has been representing at various forums to enhance the pecuniary jurisdiction of District Courts in Delhi from the existing rupees twenty lakh to rupees two crore in view of the fact that the property value has increased manifold. In the present economic scenario, monitory jurisdiction has become so low that even a case pertaining to very small property has to be filed before the Delhi High Court. On the other hand, there are few other grounds also to enhance the pecuniary jurisdiction. On the other hand, it has increased the workload of the Delhi High Court. Poor people who are living in the far-flung areas of Delhi have to cover a considerable distance for approaching the High Court to seek justice in their cases. The Government of NCT has considered the request of the Bar Association, Delhi and requested the Central Government to consider and convey approval for enhancing this pecuniary jurisdiction of the High Court and District Courts in Delhi from existing rupees twenty lakh to rupees two crore. District Courts are presently functioning in six different parts of Delhi and three more are likely to come up in Delhi. There are about 11 District Courts.

Shri D. V. Sadananda Gowda

Enhancement of the pecuniary jurisdiction will facilitate access to the general public to the District Courts located within the vicinity of their locality. Keeping in view the need to provide justice at the doorsteps of the people and the proposal of the Government of NCT Delhi to enhance the pecuniary jurisdiction of the Delhi District Courts from existing rupees twenty lakh to rupees two crore, this Bill is proposed. The Bill was referred to the Standing Committee and the Standing Committee has recommended for passing of the Bill observing a few things, even though all those things are considered in the Bill. The High Court of Delhi also in a full bench, through a Resolution on 21st November, 2012, has recommended increasing of original pecuniary jurisdiction of the High Court of Delhi, as well as, District Courts under the jurisdiction to rupees two crore. Sir, the present situation arises with the increase of pecuniary jurisdiction. I hope the Members will agree with this Bill *in toto* and I pray that the Bill may be passed.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Shadi Lal Batra.

श्री शादी लाल बत्रा (हरियाणा) : उपसभापति उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे संविधान ने हमें एक बात दी थी कि न्यायपालिका से जो इंसाफ है, वह शीघ्र से शीघ्र मिले क्योंकि यह कहा जाता है कि "Justice delayed is justice denied." 1966 में दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट था, आज दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहां की आबादी इतनी बढ़ गयी, एरिया इतना चला गया और उसके लिए 8 ज्युडिशियल कोर्ट्स बन गयीं। अगर मैं उनके नाम लूं तो वे हैं, तीसहज़ारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, कड़कड़डूमा, द्वारका और साकेत। एक बात यह है कि हाई कोर्ट जो है, चारों तरफ से देखा जाए, तो इतनी दूर पड़ जाती है कि लोगों का आना-जाना मुश्किल हो जाता है। हाई कोर्ट में इतने केसेज़ पेंडिंग हैं कि 2012 में एक लाख, 15 हजार केस पेंडिंग थे और इसमें पांच परसेंट केसेज़ हर साल बढ़ रहे हैं। करीब 60 जज बनने थे, लेकिन अभी 41 जज हैं। कोर्ट्स में जज हैं नहीं, दूरी बढ़ती है, न तो उनके दरवाजे पर आम आदमी को इन्साफ मिल सकता है और ना ही जल्दी इन्साफ मिल सकता है। अगर इसके कारणों को देखें, तो सारे देश में 24 हाई कोर्ट्स हैं और चार हाई कोर्ट्स ऐसी हैं, जिनको ओरिजनल ज्युरिस्डिक्शन दे रखी है।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)** *पीठासीन हुए*]

अगर दिल्ली की हाई कोर्ट को देखें, तो 2003 से इसकी ज्युरिस्डिक्शन 20 लाख की है। उससे पहले 1970 में 50 हजार थी, 1980 में एक लाख थी, 1992 में पांच लाख थी और 2003 से 20 लाख है। आज कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि 20 लाख की कोई कीमत ही नहीं है। जजेज़ हैं नहीं, दूरी बहुत पड़ती है, इसके लिए क्या हो, इन्साफ कैसे मिले, लोगों के दिल में यह भावना कैसे पैदा हो कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो हमें इन्साफ मिलेगा।

आज दीवानी अदालतों की हालत यह है कि एक बाप सूट फाइल करता है और पोते के समय में जाकर फैसला होता है। जब फैसला होता है तो न मुद्दई रहता है, न मुदाला रहता है,

न उसकी कोई वैल्यू होती है। इसलिए जरूरी है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि जल्दी से जल्दी केसेज़ का निपटारा हो। अब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन यह कहती है कि हमारे पास ज्युरिस्डिक्शन कम है, हमारी ज्युरिस्डिक्शन बढ़ाई जाए और हाई कोर्ट यह कहती है कि यह न जाए, तो यह देखना होगा कि इन्साफ का तकाज़ा क्या है? इन्साफ का तकाज़ा एक ही है कि जो ज्युरिस्डिक्शन 20 लाख की थी, उसको बढ़ाकर दो करोड़ की कर देते हैं, तो इसमें एक होगा, जो बड़े-बड़े आदमी हैं, उनके केस जाएंगे, जिनकी वैल्यू ज्यादा होगी, उनको इस बात की भी परवाह नहीं होगी कि हाई कोर्ट में कितना खर्चा होता है, न हाई कोर्ट में जाने की परवाह होगी और वे इसके खर्चे को afford कर सकेंगे और आम जनता से दूरी नहीं होगी तथा आम जनता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी।

इसके लिए हम ऐसा काम करें कि जिसमें हाई कोर्ट की ज्युरिस्डिक्शन, वह ज्युरिस्डिक्शन हो, जिसके लिए आम आदमी को वहां जाकर ज्यादा खर्च करने की जरूरत न पड़े, ज्यादा तकलीफ न हो और अपनी सुविधा के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सके।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आज के समय को देखते हुए, हाई कोर्ट की ऑरिजनल ज्युरिस्डिक्शन दो करोड़ की कर दी जाए। इससे किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और हर मुकदमे वाले को इन्साफ मिलेगा और उसे तसल्ली होगी कि उसे जल्दी इन्साफ मिलेगा।

इसके साथ ही, मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि जब आबादी के हिसाब से हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को पावर दे रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा हो, जजेज ज्यादा हों, ताकि वहां जाने के बाद ऐसा न हो कि आसमान से गिरा और खजूर पर लटका। यहां से इसलिए जा रहे हैं कि केसेज़ का निपटारा जल्दी हो और वहां पर निपटारा जल्दी न होकर और देर से हो। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अधिक जजेज की अप्वाइंटमेंट की जाए, जजिज की संख्या बढ़ाई जाए। इसके बाद यह देखा जाए कि जो मुकदमा आता है, वह दो साल-तीन साल में खत्म हो जाए, ताकि लोगों को यह विश्वास हो सके कि हमारी अदालतें इन्साफ देती हैं और उनका अदालतों पर विश्वास बना रहे। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेज बढ़ाकर लोगों को इन्साफ देने के लिए जल्दी से जल्दी और न्यायालयों का इंतजाम किया जाए। धन्यवाद।

श्री विजय गोयल (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे दिल्ली वालों को बहुत लाभ मिलेगा। दिल्ली वालों में भी आप यह समझिए कि कम से कम 80 प्रतिशत दिल्ली की जनता इससे लाभान्वित होगी। इससे वकील भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर जो वकील हैं, वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा जजों को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी जो हाई कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर भी बहुत भार था। इस के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 5(2) को संशोधित करके हमारे मंत्री जी ने जो बिल हाउस में रखा है, उसमें '20 लाख' शब्द के स्थान पर 'दो करोड़' शब्द हो गया है। कहने के लिए यह एक छोटा संशोधन है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। मैं इसके लिए अपने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अपने कानून मंत्री श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा जी को बधाई देना चाहता हूं। गौड़ा जी को खास तौर से इसलिए कि उन्होंने बहुत pain लिया है। उपसभाध्यक्ष

[श्री विजय गोयल]

जी, मैं तो 2003 में भी वकीलों के साथ खड़ा होकर आन्दोलन करता था। उस समय भी 2003 में जब इसको 5 लाख से 20 लाख किया गया, तो हम वकीलों के समर्थन में खड़े होते थे। मुझे खुशी इस बात की है कि उस समय भी एनडीए की सरकार ने इसको पास किया था और आज भी जो इसको 20 लाख से 2 करोड़ किया जा रहा है, वह भी एनडीए की सरकार कर रही है। 2012 में हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने इसको पारित कर दिया था कि इसको 20 लाख से 2 करोड़ कर दिया जाए, पर उस समय के जो कानून मंत्री थे, कपिल सिब्बल जी, उस समय यूपीए की सरकार थी, उन्होंने पता नहीं जान-बूझ कर या किसी दबाव के कारण या किस कारण से इसको अंतिम सत्र के अन्दर रखा और वह किसी भी हालत में पारित नहीं हो पाया। आज खुशी है, इसके लिए मंत्री जी को बधाई कि उन्होंने आज हमारे सामने इसको पारित कराने के लिए रखा है। सबसे बड़ी बात है कि बार एसोसिएशन के जो समस्त पदाधिकारी हैं और उनकी जो समन्वय समिति है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक प्रेशर बना कर रखा। केवल वकीलों को ही नहीं, बल्कि जनता को भी इसका सबसे ज्यादा लाभ पहुँचा है। बार के और भी बहुत सारे नेता हैं, जिनका इसमें रोल था। इसके साथ हाई कोर्ट की भी फुल कमिटमेंट है। आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि इससे दिल्ली की लाखों जनता को लाभ होगा। मैं दिल्ली से तीन बार सांसद रहा हूँ, डेल्हाइट हूँ, इसलिए मैं आज यह कह सकता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सस्ता न्याय मिलेगा। पहले जो गरीब झुग्गी-झोंपड़ी में रहता था, जो अनधिकृत कॉलोनी में रहता था, उसको भी हाई कोर्ट के वकील के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, जिसके कारण उसको मोटी फीस देनी पड़ती थी। इसलिए आम जनता को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि उनके घर के पास जिला कोर्ट हो जाएगा। आज यहां 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किन्तु जो सेंटर्स हैं, वे 6 हैं – कड़कड़डूमा, द्वारका, रोहिणी, तीसहजारी, पटियाला हाउस और साकेत। अगर किसी आदमी को न्याय पाना है और वह गरीब आदमी है, आम आदमी है, मध्यमवर्गीय है, तो वह पास के कोर्ट में जाकर अपना मुकदमा लड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इससे स्पीडी जस्टिस होगी और न्याय जल्दी मिलेगा, क्योंकि यह अलग-अलग कोर्ट्स के अन्दर होगा। जैसा बताया गया कि हाई कोर्ट के अन्दर 1,12,000 केसेज़ हैं, जिनमें कम-से-कम 15,000 केसेज़ ऐसे हैं, जो अब नीचे के कोर्ट्स में आ जाएँगे और जिनके फैसले अब जल्द हो पाएँगे। उपसभाध्यक्ष जी, हाई कोर्ट की तारीख 6-6 महीने पर पड़ती थी। अब ये मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अन्दर ज्यादा होंगे। मैं समझता हूँ कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कम-से-कम 250 ऐसे जज हैं, जिनके पास न के बराबर काम था और हाई कोर्ट के ऐसे जज थे, जिनके ऊपर प्रेशर था। इन 250 जजों को भी अच्छा-खासा काम मिल जाएगा और हाई कोर्ट में भी लिटिगेंट्स का काम जल्दी इसलिए होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब वहां लोड कम होगा, तो वहां भी केसेज़ जल्द-से-जल्द सॉल्व होंगे। उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि केवल हाई कोर्ट का फुल कोर्ट क्या कहता है, स्टैंडिंग कमेटी ने भी जितनी रिकमेंडेशंस कीं, उनके अन्दर यही पारित किया कि इसको जल्द-से-जल्द 2 करोड़ करना चाहिए। इसलिए मैं इसके विस्तार में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को लगता होगा कि यह दिल्ली के लिए हो रहा है, जबकि मुम्बई के अन्दर पहले से यह सीमा एक करोड़ है, कोलकाता के अन्दर भी एक करोड़ है, यहां तक कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में तो यह सीमा अनलिमिटेड है, यानी दो करोड़ नहीं, अगर 5 हजार करोड़ का भी मुकदमा हो, तो इन छोटे कोर्ट्स में फैसला हो सकता है। अगर देश के चार बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अन्दर

कोई लिमिट नहीं है। सिविल सूट जितने करोड़ रुपए का भी हो, वह वहां पर फाइल किया जा सकता है। यहां तक कि जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, उसके पास भी अनलिमिटेड पावर है, किन्तु यहां पर 20 लाख तक की जो सीमा लगा रखी थी, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा था, क्योंकि दिल्ली की जनता, जो झुग्गी-झोंपड़ी में भी रहती है, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी की कीमत देखेंगे, तो वह आज 20 लाख रुपए से ऊपर ही मिलेगी। उसके लिए उसको हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। मैं समझता हूँ कि अगर आप अभी सर्किल रेट देखेंगे, तो पाएँगे कि हर आदमी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आना बहुत जरूरी है। इससे गरीबों को सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो हर 5 साल में इसका रिव्यू होना चाहिए। इसके लिए वकील आन्दोलन करें, यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए आपको एक नॉर्म बनाना चाहिए। दूसरा यह है कि इसको प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ा जाए। जैसे-जैसे महँगाई बढ़े, वैसे-वैसे इसकी सीमा बढ़नी चाहिए। जब-जब सर्कल रेट बढ़ें, तब-तब इसका रिव्यू होना चाहिए। मैं समझता हूं कि लोक सभा भी इसको जल्द से जल्द पारित कर देगी। एक बार पुनः मैं अपने मंत्री, श्री सदानन्द गौड़ा जी को और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था, 'सबका साथ – सबका विकास', जिसको उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया है। इससे दिल्ली की 80 फीसदी जनता को बहुत लाभ मिलेगा और वकीलों को अच्छा लाभ मिलेगा। इससे जजों को राहत मिलेगी, सबके लिए यह बिल अच्छा साबित होगा। हम समझते हैं कि इसको भारी बहुमत से पारित करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वैसे तो अब हम एक नॉन-प्रेक्टिसिंग एडवोकेट हो गए हैं, लेकिन हमने करीब 10 साल तक प्रेक्टिस की है।

महोदय, मैं एक बात नहीं समझ पाया कि दिल्ली में यह कानून क्यों था? हमारे उत्तर प्रदेश में, मुकदमा चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। देश के अधिकांश भागों में यही रूल है। हमारा ज्यूडीशियल सिस्टम भी यही है कि मुकदमा पहले मुंसिफ कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब हर जगह चार चरणों में न्याय मिल रहा है, तो फिर पता नहीं क्यों दिल्ली में दो चरण एकदम ही समाप्त कर दिए गए।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। मुझसे कुछ वकील साथी भी इसके लिए मिले थे, मैंने उनसे भी कहा था कि मैं इसका समर्थन जरूर करूंगा।

महोदय, यह इन्जस्टिस क्यों हो रहा है? गौड़ा जी, मैं आपसे एक बात अवश्य कहूंगा, आप सिर्फ डाकिया न बन जाइएगा। हंसराज भारद्वाज जी भी लॉ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन वे जो चाहते थे, कानून में वही तय करते थे। आज मुझे तकलीफ होती है, जब आप लोग सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं, इसीलिए हम यह बिल पेश कर रहे हैं। हमारे ये दोनों हाउस, जिनको स्वयं संविधान ने कानून बनाने का अधिकार दिया है, अगर उनको कोर्ट निर्देश दे रहा है, तो यह तो उचित नहीं है। यह कैसे न्यायसंगत है? जब हम लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है।

श्रीमन्, हर रोज़ हम अखबारों में, पत्रिकाओं में यह पढ़ते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। यह तो ऐसा हो गया, जैसे हम चपरासी हो गए और जज हमको फटकार

[श्री नरेश अग्रवाल]

लगा रहे हैं। यह ऐसी बात है, जिसे सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मुल्जिम नहीं हैं और जिनको कोई तलब नहीं कर रहा है, उनको कोर्ट ने सम्मन दे दिया।

एक और नया सिस्टम चालू हो गया है, कोर्ट की ऑब्ज़र्वेशन में अमुक जांच हो। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस का ऑब्ज़र्वेशन करेगा, तो फिर कौन सी अदालत उस आदमी को बेल देगी? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑब्ज़र्वेशन करने लगेंगे, तो फिर इंक्वायरी ऑफिसर की क्या हैसियत रह गई? हमारे कांस्टिट्यूशन में आईओ की व्यवस्था की गई है। वह आईओ इसीलिए बनाया गया था, ताकि वह इंडिपेंडेंट जांच कर सके, लेकिन अब यह नया सिस्टम शुरू हो चुका है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि किस आर्टिकल में कोर्ट यह निर्णय देती है कि हम अपनी सुपरविज़न में इसे देखेंगे, यह हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

महोदय, आप देख लीजिए, आज अगर सीबीआई कोई मुकदमा करती है, पहले तो मीडिया से उसे हाई प्रोफाइल करा देती है। अगर सीबीआई की सारी चीज़ें मीडिया से इतनी हाई प्रोफाइल हो जाएंगी, तो क्या फिर किसी सेशन कोर्ट जज की यह हैसियत रह जाएगी कि वह उस मुकदमे में न्याय दे दे? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कम से कम इन सीबीआई की अदालतों में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज से नीचे के किसी जज को मत रखिए। अगर आप इसमें सेशन जज को बना देते हैं, तो ऐसे केस में सेशन जज से कभी न्याय नहीं मिल सकता है। आप स्वयं देखिए, आज जो नीचे हो रहा है, उसकी क्या स्थिति हो रही है।

पहले एक नारा चला था, "न्याय चला निर्धन से मिलने" यानी न्याय पुअर मैन से मिलने चला है। उस समय इसके बैनर भी लगाए गए थे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि "न्याय चला धनवान से मिलने"। क्या पैसे के बिना कोई मुकदमा लड़ा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई गरीब आदमी वकील कर सकता है? आज मैं तहलका में पप्पू यादव का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को हमने दो करोड़ रुपये दिए, तब वह हमारे मामले में खड़ा होने को तैयार हुआ।

श्रीमन्, अगर एक पेशी का दो करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा, एक पेशी के पांच-पांच लाख रुपये हाई कोर्ट में देने पड़ेंगे, तो गरीबों को न्याय कहां से मिलेगा? आज हमारे देश में कारागारों की जो हालत है, उसे आप देख लें। जो गरीब आदमी हैं, वे जेल में सिर्फ इसीलिए पड़े हुए हैं कि उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। तमाम ऐसे लोग पड़े हुए हैं, जिन्हें जितनी सजा होनी चाहिए थी, उतनी हो चुकी है, वे उतनी जेल काट चुके हैं, लेकिन उनकी जमानत लेने वाला ही कोई नहीं है। आप क्यों नहीं उनके लिए कोई एक डिसीज़न लेते हैं? वैसे भी जेलों में three times capacity से ज्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन आप कोई निर्णय ही नहीं ले रहे हैं, राज्य सरकारें भी निर्णय नहीं ले रही हैं। ज्यूडिशियरी की एक अजीब स्थिति खड़ी हो गयी है। मैंने तो ज्यूडिशियरी की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी थी। जो पेंडेंसी है, वह आप देख लीजिए। 2013 तक की यह फिगर है कि सुप्रीम कोर्ट में आज 64,919 केसेज़ पेंडिंग हैं। पूरे देश में, हाई कोर्ट में 44.5 लाख की फिगर है, जबकि इलाहाबाद में 10 लाख है। यूपी के इलाहाबाद में यह 10 लाख है।

सर, सबके पास पीआईएल सुनने के लिए बड़ा समय है। पीआईएल पेशेवर लोग कर रहे हैं। कुछ लोग पीआईएल के एक्सपर्ट हो गये हैं। पीआईएल क्यों हो रही है, अब यह सभी लोग जानते

हैं। आप पीआईएल पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं? अगर थोड़े दिनों बाद पीआईएल के नाम पर यह हो गया कि पार्लियामेंट में एमपी की गाड़ी सीधे क्यों जा रही है, पीआईएल कर दीजिए, रोक देंगे कि साहब, जो एमपी है, उसको बाहर उतरना पड़ेगा और आगे पार्लियामेंट में पैदल जाना पड़ेगा। जब नाली बनाने की बात, सफाई की बात, मच्छर कैसे हैं, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ऐसे मामलों पर यह होगा, तब फिर सरकारों का काम क्या रहेगा? यह एक अजीबोगरीब स्थिति हो रही है। पीआईएल एक्सपर्ट्स के बोर्ड लगे हुए हैं। यह मैं देख रहा हूँ। मैं तो ऐसा अपने यहां भी देखता हूँ। तो आप सिस्टम में कहीं बदलाव लाइए।

आपको इतना बड़ा जनादेश मिला और जनादेश मिलने के बाद आप रोज कांग्रेस वालों से कहते हैं कि मैं आपका बिल ला रहा हूँ। तो उन्हें तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तब आप भी रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाइए, अगर उन्हीं के बिल्स आपको लाने हैं, आपको कोई नया सिस्टम नहीं लाना है। विजय गोयल जी अभी कह रहे थे और अपनी सरकार की तारीफ किए जा रहे थे, तो उनके बिल्स क्यों ला रहे हैं? आज भी आपने जो एक संवैधानिक बिल पास किया, एक-एक अक्षर उनका किया, चार अमेंडमेंट्स जो भी किए, ...(**समय की घंटी**)... तो उसमें 'सुषमा स्वराज' नाम पड़ना था, चूँकि वे मिनिस्टर थीं और 'सलमान खुर्शीद' नाम कटना था। तो आप कौन-सा बदलाव कर रहे हैं? आप बड़ी छाती पीटते हैं कि प्रधान मंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं मंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ। तो आप तारीफ क्या कर रहे हैं? आप उसी लकीर को घसीट रहे हैं, वही लकीर पीट रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... जिन्दगी में एक बात याद रखिए। राजनीति में जो बड़ी लकीर खींचता है, वह राजनीति में जिन्दा रहता है। मेरा मानना है—जो चर्चा में रहेगा, जो पर्चा में रहेगा और जो खर्चा में रहेगा, उसको राजनीति में कोई मार नहीं सकता है। बदलाव के लिए तैयार होइए, फेस करने के लिए तैयार होइए। अगर आप तैयार नहीं हैं और आपको वही लकीर पीटनी है, तो आपकी मरजी, जो चाहे करिए, लेकिन जनता बहुत दिनों तक माफ करने वाली नहीं है। गलतफहमी निकाल दीजिए, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, दिल्ली के रिजल्ट के बाद आपको सोचना चाहिए। विजय गोयल जी, हर्ष वर्धन जी भी बैठे हैं, चलिए, आप सबने बीजेपी को हराया, अच्छा काम किया, कम से कम एक डिक्टेटर को तो रोका। मैं पोलिटिक्स में ऐसे लोगों के बड़ा खिलाफ हूँ, जो अपनी पूरी जिन्दगी में सरकारी कर्मचारी रहे, अधिकारी रहे और एक दिन में मालूम पड़ा कि वे हमारे नेता हो गये। तमाम गवर्नर्स ऐसे लोग बना दिए जाते हैं, कल तक हमारे सामने जी हुजूरी करते थे और मालूम पड़ा वे गवर्नर हो गये और चीफ मिनिस्टर, जो पापुलर चीफ मिनिस्टर है, वह उनके यहां हाजिरी देने जा रहा है। हमारे यूपी में एक व्यक्ति गवर्नर बना दिए गए, जो डीएसपी थे। जो इंदिरा गांधी की सिक्युरिटी में डीएसपी थे, उनको आपने यूपी का गवर्नर बना दिया और यूपी का चीफ मिनिस्टर, जो 21 करोड़ की आबादी से जीत कर आता है, वह उनके सामने हाजिरी दे, यह लानत है। इन चीज़ों में बदलाव कीजिए और इसमें कहीं न कहीं सोचिए। ...(**समय की घंटी**)... मैं चाहूँगा कि आप जब जवाब दें, तो इन सब चीज़ों पर कोई निर्णय दें। यह तो एक छोटा सा अमेंडमेंट है। मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हूँ कि दिल्ली में यह क्यों था, आप पूरे देश में यह करिए, सिर्फ दिल्ली क्यों है, कि पहले आप सिविल कोर्ट में जायेंगे, फिर आप हाई कोर्ट जायें और तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। आप बस न्याय जल्दी दिला दीजिएगा। मैं खुद ही अपना एक मकान खाली कराना चाह रहा हूँ। तीन साल हो गये हैं, तारीखें ही बढ़ती जा रही हैं। मैं हरदोई में अपना मकान खाली कराना चाहता हूँ, लेकिन तीन साल हो गये और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो न्याय तुरन्त निर्धन को भी मिले और न्याय जल्दी भी हो जाये, ऐसा तरीका कर दीजिए। धन्यवाद।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): उपसभापति महोदय, पिछली बार जब यह बिल सदानन्द गौड़ा जी ने रखा था, तो मुझे कष्ट है कि इसको मैंने ही डेफर करने के लिए कहा था। चूँकि लॉ कमिशन की रिपोर्ट आनी थी, तो मैंने ही डेफर करने के लिए कहा था। तो उसके बाद मुझको कई बार दिल्ली के जो वकील साहिबान हैं, उनके रोष का मुकाबला करना पड़ा। तब भी मैंने उनसे वायदा किया था और फिर मैंने गौड़ा साहब से भी निवेदन किया कि यह मेरी वजह से इतना समय लगा, तो मैं उसके लिए बड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज वह बिल आ रहा है और मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। बाकी बातें भाई नरेश जी ने और दूसरे साथियों ने कही हैं। यह तो एक अच्छा काम दिल्ली वालों का हो ही गया। मैं अपनी पीड़ा पर भी आना चाहता हूँ, जिसका जिक्र नरेश जी ने किया था और मैंने इस विषय में एक चिट्ठी माननीय मंत्री जी को लिखी थी। कई बार हमने भी, सतीश जी ने भी, समाजवादी पार्टी के मित्रों ने भी और बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया है। पांच-छह करोड़ की आबादी पश्चिमी यूपी में रहती है। मैंने उस विषय में आपको पत्र लिखा, तो आपका जवाब मुझे मिला है कि Allahabad High Court vide its letter dated 10.01.2015 has intimated that it has referred the issue to the Administrative Committee comprising nine senior Judges of the High Court, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नौ जजों को इन्होंने सौंप दिया कि मान्यवर, क्या आप हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी यूपी में बनाना पसंद करेंगे? वह जान दे देंगे, तो भी यह बनाना पसंद नहीं करेंगे। वे सब इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज हैं। मतलब यह तो वही हो गया, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मछलियों की रखवाली के लिए जैसे बगुले बैठा दें आप। वह इस काम को क्यों करेंगे?

सदानन्द जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जूडिश्यरी की कोई रिफॉर्म कमेटी बनाइए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को रखिए। एक-दो आदमी नहीं, बल्कि डा. सम्पूर्णानन्द, जो हमारे यूपी के दूसरे मुख्य मंत्री थे, उनसे लेकर, चौधरी चरण सिंह से लेकर कोई बचा ही नहीं है, राजनाथ सिंह जी से लेकर नारायण दत्त तिवारी जी, सब लोगों ने कहा है। आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आई। असल दिक्कत यह हो गई है, जब तक पश्चिमी यूपी में ऊंचे पैमाने पर हिंसा नहीं होगी, आप यह नहीं बनने देंगे। मुझे तेलंगाना के मित्र बता रहे थे, हाई कोर्ट की बेंच उनके राज्य में बननी चाहिए, वहां से उन्होंने आन्दोलन शुरू किया। आपने राज्य दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच नहीं दी। मैं आपकी बात को ही contradict करना चाहता हूँ।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): इस पर कमीशन बैठा और कमीशन ने रिपोर्ट दी है।

श्री के. सी. त्यागी : हां, कमीशन ने रिपोर्ट दी है। आपने मुझे बहकाने के लिए कह दिया, लेकिन मैं बहकूंगा नहीं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): त्यागी जी, समय हो रहा है।

श्री के. सी. त्यागी : सर, इतनी जल्दी समय कैसे हो गया?

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप कितना बोलेंगे, यह मुझे नहीं पता। कृपया आप conclude कीजिए।

श्री के. सी. त्यागी : सर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उसी पर खत्म करना चाह रहा

हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं तीसहजारी पर बोल चुका, मैंने इसको सपोर्ट कर दिया। मैं अपनी हजारी पर तो आ जाऊं जरा। अब इन्होंने कहा है कि यह जो वेस्टर्न यूपी का मामला है, सतीश मिश्रा जी की पार्टी, बहन जी की पार्टी, जो बीएसपी है, सुबह वाला विवाद न हो जाए, इसलिए मैं अपने आपको correct कर रहा हूँ, बीएसपी ने कह दिया, सपा ने कह दिया। आपकी पार्टी के सारे एमपीज़, वेस्टर्न यूपी के, सतीश बालियान के घर पर मिल कर, उन्होंने प्रस्ताव करके आपको भेजवा दिया। हमें तो आपके यहां की भी खबरें रहती हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चंद्र मिश्राः इसमें कमीशन बैठा था और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

श्री के. सी. त्यागी : क्या आप चाहते हैं कि हिंसा हो, क्योंकि इस समय उसके बगैर इस देश में कोई चीज नहीं मिलती। आपको जानकारी है कि वेस्टर्न यूपी के वकील कितने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, नरेंद्र कश्यप जी practicing advocate हैं, वहां 40 सालों से आंदोलन चल रहा है। ठीक है, अगर आप यही रास्ता चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी के लोग जब तक हिंसा नहीं करेंगे, लोग मरेंगे नहीं, तब तक आप यह नहीं देंगे। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नौ जजों को बैठा करके आप हम लोगों को कैसे फैसला दिलवा देंगे, यह तो आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि reorganisation of the State की कमेटी जो recommend करेगी, यह बिल्कुल गलत है। आपने रांची में कैसे बना दिया था?

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): त्यागी जी, आपका तीन मिनट का समय था।

श्री के. सी. त्यागी : सर, मैं बिल्कुल समाप्ति पर आ गया हूँ। आपने रांची में कैसे बनाया? आपने महाराष्ट्र में कैसे बना दिया? इस संबंध में इतनी बड़ी रिपोर्ट है, जिसको बार-बार पढ़ते-पढ़ते मैं थक भी गया हूँ। आप एक काम कीजिए, इलाहाबाद हमारे यहां से 712 किलोमीटर है और दिल्ली 50 किलोमीटर है। अभी हमारे दोनों मित्र बैठे हुए हैं, इनमें से कोई न कोई हमारी वोटों से मुख्य मंत्री बन जाएगा । आप वेस्टर्न यूपी के गाजियाबाद को एनसीआर में मिला दीजिए न। हर्ष वर्धन जी और विजय गोयल जी, हम बिना मतलब के उसको सपोर्ट नहीं करते, हमने तो अरुण जी से भी कहा। मैं on record कहना चाहता हूँ कि निजी बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के बजाय आप मजबूत फैसला लीजिए। हमारे पश्चिमी यूपी के एमपीज़ प्रधान मंत्री से मिले। पश्चिमी यूपी के सारे के सारे एमपीज़ बीजेपी के हैं, तो भी उनके साथ ये ज्यादती करने को तैयार हैं। अगली बार क्या वहां से ज़ीरो लेना चाहते हैं? यह हमारे पेट से, हमारी रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। आप कल्पना कीजिए, डा. अम्बेडकर ने कहा था—सबको न्याय, सस्ता न्याय। वाइस चेयरमैन साहब, क्या यह सस्ता न्याय है? अगर एक गरीब किसान, मजदूर या एक छोटा व्यापारी इलाहाबाद जाएगा, वहां जाकर किराये का मकान लेगा, वहां ट्रेन से आएगा-जाएगा और इस महँगाई में उसका खाना-पीना, अगर इन सब का खर्च जोड़ लिया जाए, तो उसकी केवल एक तारीख का खर्च ही 10-20 हजार रुपये का बैठेगा। क्या यह गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? यह अन्यायपूर्ण कार्य है। गौड़ा साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके – आप हर चीज़ में कहते हो कि by the grace of holy Prime Minister, तो इस काम को भी आप by the grace of holy Prime Minister क्यों नहीं करते? आप हर चीज़ में तो कहते हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी की अनुकम्पा से, तो इसमें अनुकम्पा में क्या दिक्कत है?

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा): प्रधान मंत्री जी आपके यहां से चुनकर आए हैं, आपका काम हो जाएगा।

श्री के.सी. त्यागी: नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक वहां हिंसा नहीं होगी, मैं वार्न करना चाहता हूँ, गौड़ा जी, नोट कर लीजिए, एक दिन आएगा जब हिंसा होगी, वहां से ट्रेनें नहीं आएँगी। सारा दूध वेस्टर्न यूपी से आता है, वह दूध नहीं आएगा, मक्का नहीं आएगी, गेहूँ नहीं आएगा, गन्ना नहीं आएगा, उसके बाद आप गाजियाबाद में जाकर घोषणा करोगे कि ये लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I rise to speak on the Delhi High Court (Amendment) Bill, 2014. The High Courts are generally considered courts of appeal and for enforcement of Fundamental Rights under Article 226 of the Constitution of India. Hence, High Courts, particularly those having original side jurisdictions, are also adjudicating civil suits like the courts below. Sir, this requires to be discontinued. The colonial legacy of the original side jurisdiction in some of the High Courts must be done away with. This Bill is a very good initiative to fast-track the judicial process, as it permits civil suits up to ₹2 crore to be heard by the eleven District Courts instead of the Delhi High Court. This move will help litigants who will no longer need to travel to the High Court and can instead go to one of the District Courts located across the city. This Bill is going to affect 12,211 cases pending so far in the High Court.

Sir, I wish to add here about the slow judicial process of this country where a litigant has to struggle to get his case cleared from one court to another. In this scenario, the Government should bring in uniformity in the pecuniary jurisdictions of High Courts across the country. Sir, in some High Courts, this limit is ₹1 crore and in some others, it is ₹2 crores. In this Bill itself, they are increasing it from ₹20 lakhs to ₹.2 crores. Merely upgrading Delhi High Court's jurisdiction or any particular High Court's jurisdiction will not be enough for the eradication of such a problem. While the Standing Committee gave its approval on this Bill, there was some doubt raised regarding this Bill from the Delhi High Court Bar Association. This was from the Secretary of the Association and I don't want to go into the details. But when a good Bill like this is brought in, the Government should take all the stakeholders into confidence on the pros and cons of the concerned Bill. Sir, for the past two weeks, the learned advocates of the District Courts in Delhi have resorted to cease work. I believe that once this Bill is passed today, the learned advocates will resume their work in the interest of the litigants. I once again thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri S. Muthukaruppan. Please take three minutes only.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to my leader, Dr. Puratchi Thalaivi, hon. Amma, and, also to you for giving me the opportunity to speak on the Delhi High Court (Amendment) Bill, 2014.

Sir, the High court of Delhi has ordinary original civil jurisdiction in respect of suits involving value of ₹20 lakhs and above. This has resulted in many small cases involving even small property disputes to be filed before the Delhi High Court. This increases the workload of the Delhi High court, and, to seek justice, poor people living in the National Capital Territory of Delhi also have to cover considerable distance to approach the Delhi High Court. The enhancement of pecuniary jurisdiction of District Courts in Delhi was sought by the practicing advocates and the litigants as well.

Also, the Co-ordination Committee of the Bar Association of Delhi requested to enhance the value from existing ₹20 lakhs to ₹2 crores, which is a welcome measure. With the passing of this Amendment Bill, the pecuniary jurisdiction of Delhi High Court will rise to ₹2 crore and above whereas the District Courts and the City Civil Courts will henceforth handle civil cases of the value from ₹5 lakhs to ₹2 crores.

Sir, I would like to make an observation. Whether the increase in the pecuniary jurisdiction will result in filing of more cases before the District Courts, and, if so, whether the District Courts have sufficient number of judges to dispose of the cases expeditiously.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Continuous reading is not allowed; please avoid this.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: As far as my State, Tamil Nadu, is concerned, under the valuable guidance of my leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, we have taken many steps. In the State Budget for the year 2015-16, a sum of ₹809.70 crore has been provided for the judiciary. Tamil Nadu can proudly declare that out of 986 subordinate courts functioning in the State, 87.78 per cent are located in their own buildings and only 12.22 per cent operate from rented premises.

Sir, in the presence of the hon. Law Minister, I would like to say that, in fact, under the Centrally-sponsored scheme for enhancing judicial infrastructure, no funds were released for the State of Tamil Nadu in the years 2010-11 and 2011-12. I urge upon the Government of India, and, I request the Law Ministry to release sufficient funds for the State of Tamil Nadu for judiciary.

Under the guidance of my leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, in the last four financial years, the Tamil Nadu Government has ordered the constitution of 170 new courts in all, which include 65 special courts for matters relating to land acquisition

[Shri S. Muthukaruppan]
and motor vehicles accident compensation, etc., 46 family and *mahila* courts, and, 26 judicial Magistrate courts and Munsif courts.

In addition to this, the Government of Tamil Nadu has sanctioned 90 evening courts over and above the 53 evening courts, which are already functioning. Recognizing the need for recruiting more judges in Tamil Nadu, we have recruited 178 civil judges in the year 2012 to 2013. This has drastically brought down the number of vacancies in the lower judiciary. ...*(Time-bell rings)*... A similar recruitment of 162 civil judges is under progress. Sir, the AIADMK party is concerned about strengthening judicial infrastructure.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please make specific point and conclude.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, I will take one more minute. Sir, one hour time has been allotted to this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Everybody is opposing the continuous reading. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवाल : एक बात और है। दूसरे के विचार कोई दूसरा आदमी रख सकता है सदन में? कंटीन्यूअस रीडिंग का मतलब हमारे विचार नहीं हैं। हम किसी दूसरे के विचार पढ़ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : हम कहते हैं तो उसको कोई सुनता नहीं है और जब हम बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन नियम में है कि पढ़ना नहीं चाहिए।

श्री नरेश अग्रवाल : वही मैं कह रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): हमने दो बार याद दिला दिया, उसके बाद कोई पढ़ रहा है तो मैं क्या करूं।

SHRI NARESH AGRAWAL: Continuous reading is not allowed. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यह तो उनका अपना रुख होना चाहिए।

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Most of the Members do like that. ...(*Interruptions*)... When I am reading, why are you asking me to... ...(*Interruptions*)... I don't understand this. ...(*Interruptions*)...

SHRI NARESH AGRAWAL: That is not proper. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): What is wrong in this? ...(*Interruptions*)...

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Why are you interrupting? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): It is in the procedure. ...(*Interruptions*)...

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: If we are able to read ...(*Interruptions*)... If we are able to read, we are able to speak also without papers. We are able to speak. We are capable of speaking. Please don't interrupt. ...(*Interruptions*)...

SHRI NARESH AGRAWAL: Please address the Chair. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): It is in the procedure. ...(*Interruptions*)... Continuous reading is not allowed.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: I don't understand this. While making points, if any point is omitted, we are liable to answer ...(*Interruptions*)... That is why, we are reading this. I am frankly telling the House.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Dates and particulars have to be given. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. Five minutes are over.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, our repeated request to authorize the use of Tamil language in the High Court of Madras has not been responded favourably. I urge upon the Government of India to see to it that Tamil is made a court language of Madras High Court. Lastly, I whole-heartedly welcome this Bill. I thank hon. Amma and also the Vice-Chairman for giving me the opportunity.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : श्री वीर सिंह जी। आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 का और संशोधन करने वाले इस विधेयक पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, आपने मुझे विधेयक पर बोलने का समय दिया, इस के लिए मैं आपका व अपनी पार्टी अध्यक्षा बहन कु. मायावती जी का अत्यंत आभारी हूं।

महोदय, दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा साथ ही दिल्ली के 11 जिला न्यायालयों के "मूल आर्थिक क्षेत्राधिकार" को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने के प्रयोजनार्थ लाया गया है। उक्त क्षेत्राधिकार प्रवर्द्धन से दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यभार में तथा वहां के लंबित मामलों में कमी आएगी। इससे मुकदमेबाजी के खर्च में कमी आएगी और वादी को जल्दी इंसाफ मिल सकेगा।

महोदय, दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान 60 न्यायाधीशों में से 6 न्यायाधीशों को मूल पक्ष पर दीवानी मुकदमों के न्याय निर्णयन का दायित्व सौंपा गया है। वर्तमान में दिल्ली न्यायालय

[श्री वीर सिंह]

में 41 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की 19 रिक्तियां विद्यमान हैं और दीवानी पक्ष के 1,12,211 मुकदमे लंबित हैं।

महोदय, दिल्ली को प्रशासनिक सुविधा के लिए 11 जिलों में विभाजित किया गया है। यहां जिला न्यायालय 11 जिला न्यायाधीशों समेत 250 न्यायिक अधिकारियों के साथ तीस हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, कड़कड़डूमा, द्वारका और साकेत सहित 6 न्यायालय परिसरों में कार्य कर रहे हैं। इस विधेयक के पारित होने पर 2 करोड़ रुपए से अधिक के सिविल वादों और कार्यवाहियों को दिल्ली से संबंधित ग्यारह जिला न्यायालयों में स्थानांतरित या दायर किया जा सकेगा। मेरा मानना है कि जिला न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को 2 करोड़ रुपए बढ़ाने से उच्च न्यायालयों पर बोझ कम होगा और वादकारियों को सुलभ न्याय मिलने में सहायता मिलेगी।

महोदय, देश में विद्यमान 24 उच्च न्यायालयों में से केवल 4 उच्च न्यायालयों—दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को मूल पक्ष पर आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा बाकी के 20 उच्च न्यायालयों में मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : वीर सिंह जी, conclude कीजिए।

श्री वीर सिंह : इस आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा को उस संविधि या अधिकार पत्रों के माध्यम से लागू किया गया है जिस के तहत संबंधित या अधिकार पत्रों में संशोधन कर के इस सीमा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जो उन क्षेत्रों में सम्पत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी पर निर्भर करती है, जिन पर यह न्यायालय उनके क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। दिल्ली में संपत्ति की दरों में वृद्धि को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ दिल्ली के जिला न्यायालयों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक हो जाती है। इस के फलस्वरूप लंबित वाद संबंधित जिला न्यायालयों में वितरित कर दिए जाएंगे और वादकारियों को समय पर उचित न्याय मिल सकेगा।

मैं विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि—

(1) देश में सभी उच्च न्यायालयों के आर्थिक क्षेत्राधिकार में समानता लायी जाए।

(2) चार्टरित उच्च न्यायालयों के मूल क्षेत्राधिकार की संवीक्षा व समीक्षा कराई जाए जिस से वहां वादों की संख्या में कमी आ सके।

(3) जिला न्यायालयों में समुचित अवसंरचना को स्थापित किया जाए जिस से न्याय प्रणाली प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा सके।

(4) जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में "ई कोर्ट" की स्थापना की जाए जिस से वादों का त्वरित निपटान संभव हो सके।

(5) सभी राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाए जिन की राज्यों में अभी संख्या 151 ही है, जिस से आवंटित वादों की संख्या उच्च न्यायालयों में कम हो सके।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : धन्यवाद, वीर सिंह जी।

श्री वीर सिंह : महोदय, इस के साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि न्यायालयों में जो निर्णय होते

हैं, उन्हें नेट पर डाल दिया जाना चाहिए जिस से कोई भी उस निर्णय को देख सके। इस से लोगों को वाद कार्यों में बहुत सुविधा मिलेगी और न्यायालयों में कार्य का भार घटेगा तथा जनता को शीघ्र न्याय मिलेगा। महोदय, कोर्ट फीस भी कम की जाए, जिससे कि गरीब लोग भी अपने वादों का निस्तारण कर सकें। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग को कई बार दोहराया है, मैं भी इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। महोदय, इस संबंध में स्थापित कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है।

मैं इन्हीं कुछ मांगों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, I rise to support this Bill. But I want to mention one thing before the Government and to the Minister, through you, Sir. The Government is only taking temporary measures. *Ad hoc* mechanism is going on in the country. This is a Bill wherein, everyone knows this, the pecuniary limit of ₹20 lakh is to be increased to ₹2 crore for Delhi civil courts. I support the issue of pecuniary jurisdiction that it should be increased. At the same time, the number of judges' vacancies in Delhi itself – it is there in other High Courts also – are to be filled; the pendency of cases is to be reduced and the facilities of High Courts is to be increased. Earlier also, the Minister replied and we were very sad to hear that High Court bench at Trivandrum, the Capital city of Kerala, is not accepted by the Minister. Still that situation is continuing. Regarding the *ad hoc* mechanism of the Government, I want to say something about the existing system of Civil Procedure Code. As per the Civil Procedure Code, entire district courts in the country are free to try cases upto any amount involved in it. Then why in Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai this is happening? There were chartered courts, during British period, for the cities. Delhi was a part of Lahore Court. Chennai, Mumbai, Madras and Kolkata are also having the same problem. In the city, the limit is there. So, I think, the Minister will say something about the implementation of a uniform system in the country. Why are you not accepting the Civil Procedure Code (CPC) throughout the country? If CPC is there throughout the country, why are you amending it every time? Now, we are amending the Delhi High Court Act because Delhi is under the Central Government. It is having its own limitations, it is not a total State. In Chennai, Kolkata and Mumbai, State Assemblies are increasing the pecuniary jurisdiction every time. So, civil courts across the country should have the same pecuniary jurisdiction as other courts have and the system of augmenting the limit every ten years or five years has to be changed. So, I am requesting the Government, and I hope that the Government will bring some legislation to amend the existing system of this *ad hoc* mechanism. Thank you, Sir.

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जितनी ज्यादा जुडिशियरी केसेज की पेंडेंसी कोर्ट में हो गई है, उस वजह से जनता को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस लिहाज से दिल्ली हाई कोर्ट (अमेंडमेंट) बिल एक अच्छा कदम है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में प्रोपर्टी कितनी महंगी हो चुकी है। ऐसे में एलआईजी फ्लैट, जिसकी कीमत बीस लाख रुपए से ऊपर होती है, उसके मामले भी हाई कोर्ट में चले जाते हैं। इसलिए यह हाई कोर्ट के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बीस लाख रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करने की आज के समय की मांग है। इस बिल के कानून बनने के बाद दो करोड़ रुपए से नीचे के सभी मामले जिला अदालतों में निपटाए जा सकेंगे। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। मैं अपनी पार्टी बीजेडी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, this is a very small amendment but it gives a very good performance in the courts section for the people. It has been stated in the Bill that in order to relieve the workload of the Delhi High Court, the pecuniary jurisdiction of High Court has been enhanced from ₹20 lakh to ₹2 crore. It seems to be a very high jump, but what to do? Nowadays, the lower courts are themselves giving judgment; the penalty itself is ₹100 crore or more than ₹100 crore. So, whether this Bill will not pave the way for ...(*Interruptions*)...

SHRI K.N. BALAGOPAL: Is it legal to have a penalty of ₹100 crore? Whether such jurisdiction is there for the lower courts ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please address to the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, he said that the lower courts are giving a penalty of Rs.100 crore. Whether it is legal ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is not yielding. Please sit down.

DR. K.P. RAMALINGAM: I will answer for him also. The courts are themselves giving penalty for more than ₹100 crore. So, if they are increasing the pecuniary jurisdiction from ₹20 lakhs to ₹2 crore, so what? That is what I am answering. Whether this will not pave the way for additional workload at the district courts level. Because the number of cases pending in trial courts is huge across the country. That is what Mr. Balagopal also mentioned. This is because of inadequate infrastructure as well as staff in the lower judiciary. This is applicable to all the States, not Delhi alone. The Government should take a holistic approach instead of a piecemeal approach in deciding the pecuniary jurisdiction of High Courts. Why am I saying this? Tomorrow, some bar associations of High Courts or District Courts may come forward with the same request. The Government's move will certainly backfire. As I have already said, the pendency of cases at trial stage is very huge.

The justice delivery system will be hampered by ulterior motives. I request the Minister to speed up the process of filling up all the vacancies. I also request the Minister to consider uniformity across the nation.

Now all the High Courts have English as court language. Regional languages should be made court languages of the concerned States. In the State of Tamil Nadu, the court language of the High Court and its Bench at Madurai should be Tamil. For that, you have to come with a Bill. You are coming with an amendment Bill to raise the limit from ₹20 lakh to ₹2 crore. Like that, for court language, you have to come with a Bill. That will help the poor people and the ordinary public. You must consider this. I welcome this Bill.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, I rise in support of the Delhi High Court (Amendment) Bill. Increasing the pecuniary jurisdiction to rupees two crore is a timely and appropriate move.

Sir, unlike what some of my fellow Members said, this is not some *Achche Din*. This is actually the result of the hard work of the Standing Committee headed by Natchiappanji and before that Shantaram Naikji. It is also the result of hard work of numerous lawyers who have gone on strike and who have been agitating to ensure that this Bill actually comes through.

Sir, as we think about this whole process, this is a move to try and improve the efficiency of the legal system and to clear the backlog of cases in the Delhi High Court. When you start thinking from an efficiency point of view, one of the things you can think of is parliamentary efficiency. Can't we institute a formula whereby every five or ten years this pecuniary jurisdiction is amended according to factors like inflation rate or circle rate? All these sorts of factors can be brought in and, on an automatic basis, in five or ten years, you can change the pecuniary jurisdiction of these courts. Alternatively, as comrade Balagopal has mentioned, the Law Minister could think of working with the judiciary to try and bring about uniformity in the nature of courts and their jurisdiction across the country.

Sir, another point that I want to make is this. As we think about all these measures, we need to think about proper data. During the discussion on the functioning of the Ministry of Law and Justice, lots of issues came up relating to appropriate data. Some months ago, an NGO in Bangalore called 'Daksh' launched a website in an effort to try and get more appropriate data on pendency of cases. The Law Minister was supposed to inaugurate it. But, unfortunately, he was not able to make it and they said that if one Gowda could not do it, let another Gowda do it. So I inaugurated it. Basically, that database is revealing numerous details about hidden cases and things that have been in place for 50-odd years. We need to look at those issues and figure out efficiency measures to speed up the whole process.

[Prof. M.V. Rajeev Gowda]

Sir, one of the first things that we will discover is that if you start classifying cases, there will be a huge number of cases that include traffic challans or petty matters pertaining to the Government. These can be assigned to a separate Bench. The Minister has already made a move towards this with the creation of commercial courts. That is a very good move. That again creates a certain amount of specialisation in the way courts handle these cases. Sir, consulting some efficient experts will ensure that we will be able to have justice delivered in a timely manner rather than be delayed and denied.

Sir, I want to mention a couple of matters. One is, of course, on training of judicial officers. Today, the system of legal education has gone through a transformative change. Ten or twenty years ago we did not have national law schools. Today, we have many. They are running numerous training programmes. You have a National Judicial Academy. So, I would urge the Law Minister, through you, Sir, to work on more programmes that train judicial officers, the judges, etc., so that this whole process of disposal of cases can be improved. The way they are dealt with in the system can be improved.

Sir, the Law Minister is also from my home State, and we know that when Justice Bharucha was there, he had introduced the electronic-governance measures in the High Court. This has been a transformation. People don't have to come every day to find out when their case is listed. They can log on from their home computers or office computers and find out what is happening, when they need to come, how long their case is pending, before whom it is listed, etc. These sort of measures need to be introduced across the country. The UPA Government has brought about an e-court.gov.in measure, and that measure really has been the path breaking measure. Unfortunately, different courts in different States have adopted different standards. If the Law Minister can ensure some amount of uniformity, then, change the whole approach of the way judicial cases are managed, from one of squeezing the litigant and making life difficult, to one of facilitating, participating in the legal system to be supportive and make life easier. That will make a huge difference.

Finally, I would like to support the point raised by Tyagiji. When this Bill was postponed, it was postponed partly on the basis of what will happen to the surrounding areas.

Sir, Delhi is no longer Delhi. You are now part of the National Capital Territory Region. You have Ghaziabad and Noida in Uttar Pradesh. You have Gurgaon and Sonepat in Haryana. You have lots of other parts of the Region. Why should those litigants have to go to Chandigarh or Allahabad? Is there some way? You can either create additional Benches in the Region of NCR, or the National Capital Region,

or, can you work with those High Courts to shift some of their jurisdiction to the Delhi High Court itself? I would urge the Law Minister to explore these options.

I would commend this Bill to the House for passage. It is a move in the right direction.

SHRI K.T.S. TULSI (Nominated): Thank you, Sir. I just want two minutes.

I rise to support the Delhi High Court (Amendment) Bill, 2014, brought by the hon. Law Minister. This is a measure which will provide justice to the Delhites at their door step. Sir, decentralisation has always been the objective of the Government for over 10 years. Huge amount of infrastructure by creating additional District Courts all around has achieved hundreds of more court rooms; and there are many more Judges who are available at the District court level which will not only speed up justice but also provide them justice at their door step. The Judges at the district level have, on an average, about 26 minutes to a case as against only six Judges on the original side who sit in the High Court, who can devote approximately 20 seconds to a case. Therefore, in the Delhi High Court, when the delay in disposal of cases legion, if you file a case today, and it comes up for issues and for evidence it will be taken up ten years later because there are no Judges. Then, only the Judicial Commissioners will be recording the evidence. When the Judicial Commissioner record the evidence, the cost of justice also goes up significantly.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

I also want to commend to the hon. Minister all that is being done is to enhance the pecuniary jurisdiction to ₹2 crores.But in the mid 80s, Punjab adopted a law by which unlimited jurisdiction was provided to District Courts, and unlimited jurisdiction not only for the purpose of trial of civil suits, but also for the first appeal. Even the first appeal is being heard by the District Judge in Punjab for the last 30 years. That system has worked very well. We need not concentrate the litigation as a matter of policy in the hands of the High Court. Justice must be dispensed at the grassroots level. I, therefore, hope that the Government and the Law Minister, after the passage of the Bill, will not play any further games and that the Bill would be notified soon after it gets the assent and that it would become a law which is operative. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Mr. Rajeev Shukla; you have two minutes.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं भी इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह बहुत जरूरी है। सारे वकील आंदोलन पर हैं, हड़ताल भी है इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी सरकार इसको पास करके लागू करा सके, बेहतर होगा।

[श्री राजीव शुक्ल]

केवल एक aspect है, जिसे लॉ मिनिस्टर को देखना पड़ेगा। जो दूसरा बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ है, इस बिल से 20 लाख से 2 करोड़ की लिमिट हो जाएगी कि वे केसेज़ वहां चले जाएंगे, तीस हज़ारी को ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरा बिल है, जितने इंटरनैशनल मैटर्स हैं, इंटरनैशनल कम्पनीज़ हैं, जितने कार्पोरेट के और जितने कमर्शियल मुद्दे हैं, वे अभी भी हाई कोर्ट में जाएंगे क्योंकि तीस हज़ारी की कैपेसिटी इन मैटर्स को डील करने की नहीं है। इस प्रकार जो लिटिगेंट है, वह तीस हज़ारी और हाई कोर्ट के बीच में अभी भी भटकता रहेगा और उसको यहां भी और वहां भी, डबल खर्चा करना पड़ेगा। उसे commercial aspect के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और इस aspect के लिए तीस हज़ारी में जाना पड़ेगा। इसका जल्दी से जल्दी सॉल्युशन निकालना बहुत जरूरी है। We would not be able to achieve the desired purposes of the Bill unless the other Bill is also passed in the House.

Secondly, now everybody is demanding that matters up to the value of two crore rupees should be transferred to District Courts. That is fine. But have you looked into the aspect of corruption which is in abundance in the lower Judiciary? It is everywhere. It is a visible corruption in the lower Judiciary. That aspect also needs to be kept in mind and some mechanism developed by which Chief Justices of High Courts are able to curb corruption in the lower Judiciary. That is very essential. Otherwise, we are not going to achieve the desired purposes. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much for keeping to the time-limit. Dr. K. Keshava Rao; you would get just two minutes.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I would keep a look at the clock. Thank you very much. I would like to make just a reference. Mr. Naresh Agrawal, Mr. Tyagi, Mr. Veer Singh and others expressed their agony. For what? What really is the state of affairs of this Ministry? Not only that, when they ask for a change, when they ask for new Benches, and almost all the people who spoke, including those from Tamil Nadu talked about these things, you have to have a look into that. We really welcome this Bill. But, at the same time, think of it. These *ad-hoc* measures will not help the judicial system, because if from ₹5 lakhs, it goes up to ₹50 lakhs, from ₹50 lakhs, it goes up to ₹2 crores, then, tomorrow where would we go? We may go up to ₹5 crores. But let us have a look at it so that there is uniformity as far as these kinds of judicial things are concerned.

Sir, with your permission, I would take only one minute. An hon. Member from Tamil Nadu mentioned it. Let us take Andhra Pradesh. Even when there was undivided Andhra Pradesh, there were agitations for three years for a Bench in Andhra because people from Vizag could not go to Hyderabad. This is what was happening. Today, you have given us a separate State after a struggle; like Mr. Tyagi said, you give it only after things turned violent. You have given it and we have achieved

it; thank you very much. But for what? There is a State without a separate High Court. Can you imagine this? There must be a separate High Court for us. There is a Bill which says you would give it to us; there is Section 30. Today, because of your delay, what happens is, one great Judge comes and says that it is not clear, you have not used the word 'bifurcation'; you have said, 'a separate High Court for Andhra Pradesh and a separate High Court for Telangana'. So, he feels where is the bifurcation? Sir, we wish to thank you that, yesterday, you promised us in the Lok Sabha that you would be sitting with us and sorting out this problem. There is nothing for you to sort out because Section 31 says, "...the principal seat of the High Court of Andhra Pradesh" – which has become contentious as far as the setting up of the Court is concerned – "shall be at such place as the President may, by a notified order, appoint." This means that the President and the Government have the right to appoint or notify the place. So, please let us have a separate High Court for Andhra Pradesh.

Just one word more, Sir, because my two minutes' time is getting over. The genesis of Telangana agitation is Courts where our Mulki Rules were struck down, when 98 per cent of the cases of the Telangana people were rejected. Today let it not happen again. ...(*Time-bell rings*)... Let it not be repeated. Don't drag us to streets. Please give us a separate High Court as promised by you. Thank you, Sir.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, though it is a very small Bill, yet, the debate went on as if it was for a total reform in the legal system. ...(Interruptions)... I will answer your query.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So many advocate are waiting for getting it passed.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: That is true, Sir. But everybody was talking on something other than the Bill. They were talking about High Court Benches. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is because they fully support the Bill. So they have to talk about something else also.

DR. K.P. RAMALINGAM: That is relevant.

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): That is very much relevant.

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, he has been the Chief Minister of Karnataka and he knows the linguistic issue.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): The Lower Courts, the District Courts, have not adopted Odisha as the language.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please take your seats. Only the Minister will speak.

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: Sir, I really appreciate the concerns of hon. Members. Even though it is a small Bill, yet, they want to see that the whole legal system is reformed. For that reason, they have given various suggestions and their requests have been made on the floor of the House. So, I appreciate all the Members who have supported the Bill and who have placed their requests. Now I will not go into the details.

Some hon. Members have asked as to why there are only four Courts which have the Original Jurisdiction. Practically, under Article 225 of the Constitution, the High Courts, particularly, Presidency High Courts had the Original Jurisdiction in the pre a Independence era, and it is continuing till today since no changes have been made up till now. So, four High Courts, out of 64 High Courts, have the original pecuniary jurisdiction. As far as the contentions of Shri Vijay Goel are concerned, I do appreciate that by amending it through this Bill, the pecuniary jurisdiction of the Delhi High Court will be raised from ₹20 lakhs to ₹2 crores. Certainly, it will provide justice at the doorstep of litigants and it will help in speedier disposal of cases. Out of 60,000 cases in the High Court, more than 12,000 cases will be transferred to eleven District Courts. Automatically, the disposal of cases will be speedier. As far as the point raised by Shri Naresh Agrawal is concerned, I do consider it. I don't dispute his arguments. I do agree with things which are happening today. I don't dispute that. But the supremacy of Parliament will be taken care of. At no point of time will the supremacy of Parliament be taken for a ride. At the same time, we do not want to encroach upon the independence of the judiciary. We will take care of both the aspects and we will go ahead. Shri K. C. Tyagi and a few others from Kerala and Tamil Nadu have raised their demand that there should be a separate High Court Bench. Sir, the problem is this. The infrastructure for any High Court Bench has to be provided by the respective State Government, and the administration will be taken care of by that High Court. So, unless a proposal comes from the concerned State, it is not possible. Satishji knows it very well. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. N. BALAGOPAL: Kerala has sent it. The Court is not accepting that.

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: That is what I am saying. The Chief Minister should make a move; the Chief Justice should have a concurrence and they both should send a proposal to us. Then it will be taken up. But as far as Uttar Pradesh is concerned, recently I have received a letter from the hon. Chief Justice saying that there is no such proposal. I have received a letter. I can send a copy of it to you.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, if he needs a new proposal,...

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: No, no; I will tell you.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: There was a Commission...

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: Sir, we should find out some alternative way. At present, we know that the Chief Ministers and the Chief Justice don't go hand-in-hand. So, recently, the Chief Ministers' and Chief Justices' Conference was held at Delhi on 5th April. This matter was discussed there in detail because whenever the State is ready to provide infrastructure and other facilities, automatically the Chief Justice should give concurrence and we should go ahead. What happened in Telangana? I myself went to Hyderabad. I met the Action Committee Chairman, Shri Rajendran Reddy, and I had discussions with the people who were agitating there. Then, I called the Chief Ministers of both Andhra Pradesh and Telangana, and I tried to find out a place for a separate High Court for Andhra Pradesh. Meanwhile, one gentleman filed a Public Interest Litigation before the High Court. I think two days back some court has delivered a judgment, but I have not received the copy of it. As soon as the matter went to the court, our hands were tied. Just because it is sub judice, I could not go ahead. But, yesterday, there was a huge protest by Telangana friends. I told them that we will hold a meeting, we will sit together and we will see how it should be sorted out. Even today I assure you that after consultations with all the people, within a fortnight or so, we will find some way out. Certainly, a High Court bench is really needed for Western UP because they have to travel about 800 kilometres from the other High Courts. The litigant is put to great difficulty. But the practical difficulty is how to work it out. For that reason we have to find out some way. So we are working on it.

Sir, an issue was raised by Prof. Rajeev Gowda, that more and more IT initiatives should be taken. Computerisation of nearly 14,000 courts has been completed. Phase I is completed. We are not going to Phase II. We are taking the approval of the Government and we are going ahead. We want to see that each litigant, each advocate, even public should know the proceedings, the dates of their cases and other things. So, on all these things we are working. We are going ahead with it.

One important matter is with regard to regional language. It was discussed in Chief Ministers' and Chief Justices' Conference, but earlier a full Bench of Supreme Court said that it might not be possible. It may not be possible, but the regional language up to district courts is being used as a language. ...(*Interruptions*)... Somehow, above High Court and Supreme Court, there is a heavy demand from almost all the regional...

DR. K. P. RAMALINGAM: In Kerala it should be Malayalam, in Karnataka it should be Kannada and in Tamil Nadu it should be Tamil, in Odisha it should be Oriya.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; he told you that it is the Supreme Court's decision. ...(*Interruptions*)... Now, please sit down.

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: Sir, we have to have consultations with the Chief Justices of the High Court and the Supreme Court. We should have consultations with other stakeholders. Then only we can come to a conclusion. I don't say that we are not on it. Practically, regional languages are the need of the hour because to understand law more and more regional languages are required. But, to work it out, we have to look at some other alternative steps.

So, this Bill will, certainly, give a huge relief for litigants in and around Delhi and there will be a speedy disposal of cases.

In view of the above, I pray that the Bill may be passed.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, you have not replied to my point.

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: Sir, one minute. Last time the Bill was deferred because the Commercial Courts and Commercial Divisions of the High Courts Bill was brought before the House. Sir, even the Standing Committee observed that these should be taken together due to jurisdiction and other matters. The Law Commission also said that the Pecuniary Jurisdiction of the Commercial Benches is ₹1 crore. So, here, we are making it ₹2 crores as far as Delhi High Court (Amendment) Bill is concerned. But, in the Commercial Courts and Commercial Divisions Bill, we have defined that specific value in such a manner so that by rules we can have a parallel Pecuniary Jurisdiction across the various High Courts. So, there may be not much confusion as far as that issue is concerned. Shri Rajeev Shukla has raised a valid objection. Certainly, it will be taken care of.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, Mr. Minister, I believe, you said that the Government will take it up with the Chief Justice of India and the Chief Justices of various High Courts regarding using regional language in High Courts. You said that ...(*Interruptions*)...

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, Odia is not being used in Odisha ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: Sir, in Tamil Nadu also Tamil is not used ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please, sit down ...(*Interruptions*)... Don't you want regional language used in High Courts?

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: Mr. Deputy Chairman, Sir, in the recently concluded Chief Ministers and the Chief Justices conference the issue of using regional language has been discussion. But, we could not come to a conclusion.

So, we will try to take it up again.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But, more or less, the entire House is making that demand. You kindly note it down.

Now, the question is:

That the Bill further to amend the Delhi High Court Act, 1966, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up clause 1 of the Bill. There is one Amendment (No. 2) by the hon. Minister.

CLAUSE - 1

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I move:

(2) That at page 1, line 2, *for* the figure "2014" the figure "2015" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up the Enacting Formula. There is one Amendment (No. 1) by the Minister.

ENACTING FORMULA

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I move:

(1) That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-fifth" the word "Sixty-sixth" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

———